

10 लाख करोड़ रुपये का निवेश हासिल करने का लक्ष्य, विभागों को रोडमैप तैयार करने के दिए गए निर्देश

नई औद्योगिक नीति लाएगी सरकार

तैयारी

लखनऊ, विशेष संवाददाता। यूपी में अब 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश लाने का काम होगा। इसके लिए नई औद्योगिक नीति आएगी। इसके साथ ही प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने और ईज आफ डूइंग बिजनेस में नंबर एक पर आने की तैयारी भी शुरू हो गई है।

औद्योगिक विकास विभाग के आला अफसर राज्य में 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश लाने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। इसके लिए लखनऊ में एक भव्य ग्रांड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन होगा। राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक नीति बनेगी। वर्तमान औद्योगिक नीति में दी गई रियायतों की अवधि जुलाई में खत्म होने को है। आत्मनिर्भर युवा स्टार्टअप मिशन बनाकर 10 लाख रोजगार के अवसर प्रदान करते हुए स्टार्टअप रैंकिंग में यूपी को नंबर एक बनाया जाएगा।

यह काम तय किए गए

1. अटल इण्डस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू कर सभी मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर का नवीनीकरण
2. ओडीओपी योजना के हर जिले के एक उत्पाद को पहचान देते हुए 25 लाख रोजगार
3. राज्य में पांच विश्व स्तरीय एक्जीबिशन और आधुनिक कन्वेंशन सेंटर बनेंगे
4. सभी एक्सप्रेस वे के निकट इंडस्ट्रियल कारिडोर स्थापित होंगे।
5. हर जिले में लैंड बैंक बनेगा।
6. राज्य में तीन डाटा सेंटर पार्क स्थापित किए जाएंगे।
7. यूपी को ग्लोबल टेक्सटाइल हब बनाकर पांच लाख रोजगार सृजित होंगे।

लखनऊ, विशेष संवाददाता। प्रदेश के नए औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी का कहना है कि अगले तीन साल में निर्यात का सवा लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 लाख करोड़ रुपये करेंगे। इसके लिए विस्तृत कार्ययोजना बन रही है। हरजिले में निर्यात केंद्र खोलेंगे। साथ ही नई चुनौतियों के मद्देनजर मौजूदा निर्यात नीति में भी बड़ा बदलाव होगा। वहीं नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए 10 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे।

मंत्री ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में यह बात कही। निर्यातकों व उद्यमियों की सुविधा के लिए निर्यात ऐप बनेगा। निर्यात क्षेत्र में अपार सम्भावनाएं हैं इस फीलड में ज्यादा ध्यान देकर देश का विदेशी मुद्रा भण्डार बढ़ाने

उन्होंने कहा कि यूपी में भी इन्फ्रास्ट्रक्चर की योजनाओं की रफ्तार बढ़ाने के लिए पीएम गतिशक्ति शक्ति



हरजिले से चिन्हित होंगे एनआरआई

हर मण्डल में निवेश के लिए शहरी विकास का एक माडल बनेगा। हर जनपद के एनआरआई को चिन्हित कर उसके द्वारा अपने जनपद/मण्डल के लिए उसकी विशेषता व राय के अनुसार क्या-क्या हो सकता है- इसकी विस्तृत कार्ययोजना बनेगी। एक ऐप/ पोर्टल के अलावा इन्वेस्टमेंट एनआरआई बोर्ड बनेगा।

राष्ट्रीय महायोजना पोर्टल बनेगा। अटल औद्योगिक अवस्थापना मिशन भी शुरू होगा।

नोएडा बनेगा गेटवे ऑफ यूपी: नंद गोपाल नंदी ने नोएडा की संभावनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि वह नोएडा को गेटवे ऑफ यूपी की तर्ज पर विकसित करणेंगे। उसे इस तरह शोकेस किया जाएगा जो भी राज्य में आएगा वह प्रभावित हुए बिना नहीं रह जाएगा। यहां नए तरीके से हरियाली विकसित होगी।

बुनियादी सुविधाओं को आधुनिक तरीके से विकसित किया जाएगा। नोएडा के लिए आगामी 50 सालों का विजन डोक्यूमेंट बनेगा। नोएडा/ग्रेटर नोएडा में चल रही सभी परियोजनाओं पर एक श्वेत पत्र जारी होगा। मंत्री ने कहा कि नोएडा व ग्रेटर नोएडा के पास बकाया पैसा वापस लाया जाएगा। बिल्डर, डेवलपर के लिए समाधान योजना लाई जाएगी ताकि एक लाख लोगों के फ्लैट उन्हें दिलाए जा सकें।